

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 79/2013/भीलवाडा

मैसर्स ओंकार लाल माली
भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट, भीलवाडा

2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाडा

अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री एम.पी. शर्मा

अभिभाषक

प्रार्थीगण की ओर से

श्री आर.के. अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 21-10-16

संशोधन आदेश

यह संशोधन पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 772/2911/भीलवाडा में पारित संयुक्त निर्णय 01.11.2012 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

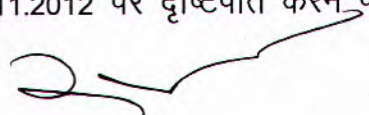
प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि व्यवहारी कार्य संविदाकर्मी (Contractor) है जिसने आलौच्य अवधि में संविदा कार्य निष्पादन में ठेका राशि पर कर मुक्ति शुल्क अदा करने का विकल्प स्वीकार कर रखा है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने समग्र ठेका राशि रूपये 84,72,325/- पर मुक्ति शुल्क @ 1.5% रूपये 1,27,085/- आरोपित किया। इसके अलावा व्यवहारी ने कज्यूअल कोमोडिटी के लिए अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत स्थापित चैक पोस्ट पर रूपये 52,506/- का बिक्री कर चुकाया था जिसका कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश में समायोजन नहीं किया। इसलिए अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील संख्या 143/RST/06-07 में निर्णय दिनांक 13.11.2007 से प्रथम बिन्दु पर अपील अस्वीकार की जबकि चैक पोस्ट पर जमा के बिन्दु पर प्रकरण बाद सत्यापन समायोजन हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित आदेश का निष्पादन आदेश दिनांक 26.11.2009 से करते हुए समग्र ठेका राशि मय मजदूरी राशि पर मुक्ति शुल्क यथावत रखा तथा चैक पोस्ट पर जमा राशि का समायोजन अस्वीकार कर दिया। जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी ने मजदूरी के बिन्दु पर पुनः अपील अस्वीकार की तथा चैक पोस्ट पर जमा के समायोजन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, अतः अपीलीय निर्णय से असहमत होकर अपीलार्थी द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक

01.11.2012 पारित करते हुए अपील अस्वीकार की है, कर बोर्ड के उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2012 में संशोधन यह संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक का मुख्य कथन है कि विभाग द्वारा स्थापित चेक पोस्ट पर रू. 52,506/-का बिक्री कर चुकाया है,जिसका समायोजन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है,इसलिए उक्त निर्णय संशोधन योग्य है। उनका कथन है कि माननीय एकलपीठ में अपने निर्णय में यह निष्कर्ष देते हुए कि "कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में सकल ठेका कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 व नियम 12(2) के तहत अन्डरटेकिंग के जरिए कर मुक्ति शुल्क जमा कराने का विकल्प लिया है इसलिए व्यवहारी द्वारा संविदा कार्य निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री पर चुकाये गये कर का कर निर्धारण आदेश में समायोजन किये जाने का अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे चुकाये गये कर का समायोजन अस्वीकार कर कोई विधिक भूल नहीं की है" । उनका कथन है कि माननीय एकलपीठ का उक्त निष्कर्ष अविधिक होने से पारित निर्णय दिनांक 01.11.2012 में रिकार्ड से परिलक्षित भूल होने से उसे संशोधित कर संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील सुनवाई के समक्ष प्रस्तुत तर्कों एवं की गई बहस पर विचार करने के पश्चात चैतन्य मस्तिष्क से निर्णय दिनांक 01.11.2012 पारित किया गया है। उनका कथन है कि व्यवहारी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र पर जिस बिन्दु को उठाया गया है, उस पर बिन्दु को अपील सुनवाई के दौरान भी उठाया गया है,जिस पर विचार करने के पश्चात ही माननीय एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 01.11.2012 पारित किया है,इसलिए उक्त निर्णय संशोधन योग्य नहीं है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का सुधार किया जा सकता है जो बिना वाद-विवाद के रिकार्ड से परिलक्षित भूल प्रकट होती है। निर्णय दिनांक 01.11.2012 ऐसी कोई भूल नहीं बताई गई है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हो, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धृत किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस के दौरान उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2012 पर दृष्टिपात करने पर



स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि अपीलार्थी द्वारा जिस तथ्य के आधार पर निर्णय दिनांक 01.11.2012 में संशोधन हेतु निवेदन किया गया है, उसी बिन्दु को अपील की बहस के दौरान उठाया गया है, जिस पर विचार करने के पश्चात ही एकलपीठ द्वारा निर्णय पारित किया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.3.2001 के तहत संविदा कार्यों के निष्पादन में अन्तर्वलित माल के सम्पत्ति में हस्तान्तरण पर कर देयता की एवज में विमुक्ति शुल्क का स्वयं विकल्प लेने पर संविदा कार्यों की कुल प्राप्तियों पर निर्धारित दर से विमुक्ति शुल्क अदा करनी होती है।

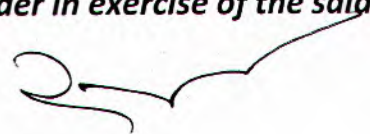
बहस के दौरान विभागीय पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) के प्रकरण में मत प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.

In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-

"8.The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.

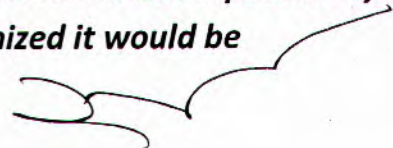
An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said



jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf."

In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held that such a power of rectification could only be exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the context of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.

Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappraisal of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be



clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नहीं जा सकता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य